



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 553]

मई दिहली, बुधवार, दिसम्बर 23 1976/ पौष 2, 1898

No. 553]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 23, 1976/PAUSA 2, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December 1976

S.O. 827(E).—The Committee on Multipurpose Workers under Health and Family Planning Programme set up on 28th October, 1972 in their report submitted on 15th September, 1973 recommended reorientation of existing Uni-purpose Workers in the field of Health and Family Planning into Multi-purpose Workers. Based on these recommendations the reorientation of the Multipurpose Workers has started. Their scope of functions is also being enlarged so that they not only provide preventive and promotive health services but also a modicum of curative services to the people in the rural areas.

2. The Group on Medical Education and Support Manpower set up on 1st November, 1974 in their report submitted in April, 1975 *inter-alia* suggested the creation of a cadre of Health Assistants to supervise the Multipurpose Workers and act as a link between them and the doctors at the Primary Health Centres. The Group also suggested that people drawn from the community itself should be given some training so as to involve them in rendering basic health services to the rural areas. Pursuant to the recommendations of the Group the Ministry has taken steps to initiate training of primary school teachers, gram sevaks, village post-masters and traditional Dais to enable them to provide primary health care in the community.

3. In view of the paucity of preventive and curative services in the rural areas it has been suggested that there is need to consider the desirability of having a part-time semi-professional worker in India who is not interested in seeking eminence in medical profession which is available through high specialisation and work in medical institutions located in urban centres. The Chinese experiment in having bare-foot doctors is cited as an example.

4. The Government of India, therefore, hereby appoint a Committee with the following composition:

Chairman

1. Shri B. Sivaraman, Member, Planning Commission.

Members

2. Shri Ghan Prakash, Secretary, Ministry of Health & Family Planning.
3. Shri B. C. Mathur, Addl. Secretary, Department of Personnel & A.R.
4. Shri P. Murari, Health Secretary, Government of Tamil Nadu.
5. Dr. G. S. Mutalik, Director of Medical Education and Research, Government of Maharashtra.
6. Dr. B. N. Tandon, Professor of Medicine, All India Institute of Medical Sciences.
7. Shri Prem Nath, Joint Secretary (Finance) Ministry of Health & Family Planning.

Member-Secretary

8. Shri C. R. Krishnamurthi, Joint Secretary, Ministry of Health & Family Planning.

5. The terms of reference of the Committee will be, following the recommendations made by the Committee on Multipurpose Workers and the Group on the Medical Education and Support Manpower, to—

- (i) examine the programme for training and employment of pragmatically trained para-medical cadres and recommend steps if any required further for early implementation of the programme;
- (ii) examine the concept of "barefoot doctors" in the context of the decision already taken with respect to community level workers and suggest any modifications they consider necessary; and
- (iii) suggest the methods of integration of the concept of the barefoot doctors with pragmatically trained para-medical cadres aimed at providing effective health, nutrition and family planning services to the rural community.

6. The Committee may consult such other persons and institutions as it consider necessary, and will submit its report to the Government within three months from the date of this Notification.

7. The expenditure on T.A. and D.A. of the officials is to be met from the source from which their pay is drawn. The T.A. and D.A. of non-officials will be governed by the orders issued by the Ministry of Finance from time to time. The expenditure involved on T.A. and D.A. of non-officials, if any will be met from the budget of the Ministry of Health and Family Planning (Department of Health).

8. This supersedes this Ministry's notification of even number dated the 15th December, 1976.

[No. Z-16018/5/76-PPH]

C. R. KRISHNAMURTHI, Jt. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1976

का० आ० 827 (अ).—28 अक्टूबर, 1972 को गठित स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुद्देशीय कार्यकर्ता समिति ने 15 सितम्बर 1973 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया था कि स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के क्षेत्र में वर्तमान एकोद्देशीय कार्यकर्ताओं को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाय कि उनसे बहुद्देशीयों की पूर्ति का काम लिया जा सके। इन सुझावों के आधार पर बहुद्देशीय कार्यकर्ताओं का पूर्ण प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। उनके कर्तव्यों का क्षेत्र भी बढ़ाया जा रहा है ताकि वे केवल रोग निरोधी और स्वास्थ्य वर्धन सम्बंधी कार्य ही न कर बल्कि गांवों में लोगों की थोड़ी बहुत रोगोपचार सम्बंधी सेवाएं भी दे सकें।

2. 1 नवम्बर, 1974 को गठित ग्रुप आफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स मैन पावर ने अप्रैल 1975 में अपनी जो रिपोर्ट दी थी उसमें उसने अन्य बातों के साथ साथ यह सुझाव दिया था कि स्वास्थ्य सहायकों का एक काष्ठर बनाया जाय ताकि बहुद्देशीय कार्यकर्ताओं के काम का सुपरविजन हो सके और वे लोग उनके और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डाक्टरों के बीच एक कड़ी का काम कर सकें। इस ग्रुप ने यह सुझाव दिया था कि लोगों के बीच में से ही कुछ व्यक्तियों को छांटा जाय और उन्हें कुछ ऐसा प्रशिक्षण दिया जाय कि वे गांवों के लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें। इस ग्रुप के सुझावों के अनुसार इस मंत्रालय ने प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों, ग्राम सेवकों, गांवों में पोस्टमास्टर्स और परम्परागत दाइयों को प्रशिक्षण देने के लिए कदम उठा लिये हैं ताकि वे समाज में प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख का काम कर सकें।

3. देहात में रोग निरोधी और उपचार सम्बंधी सेवाओं की कमी को देखते हुए यह सुझाव दिया गया है कि इस प्रश्न पर विचार करना जरूरी हो गया है कि भारत में ऐसे पार्ट टाइम सेमी प्रोफेशनल नकर होने चाहियें या नहीं जो शहरों में स्थित चिकित्सा संस्थाओं में उच्च-विशिष्टता और कार्य के जरिये उपलब्ध होने वाली चिकित्सा व्यवसाय में प्रसिद्धि प्राप्त करने में रुचि न रखते हों। यहां पर नेयरफुट डाक्टरों के चीन देश के प्रयोग का उदाहरण दिया जाता है।

4. अतः भारत सरकार एक समिति गठित करती है जिसका गठन इस प्रकार होगा :—

अध्यक्ष

1. श्री वी० शिवरमन्, सचिव, योजना आयोग

सदस्य

2. श्री ज्ञान प्रकाश सचिव, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय
3. श्री बी० बी० माथुर, अपर सचिव, कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
4. श्री पी० मुरारी, स्वास्थ्य सचिव, [तमिलनाडु सरकार]
5. डा० जी० एस० मुतालिक, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशक, महाराष्ट्र सरकार

सदस्य

6. डा० बदरी नाथ टण्डन, कार्य-चिकित्सा प्राध्यापक, ग्रहिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
7. श्री प्रेम नाथ, संयुक्त सचिव, (वित्त), स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

सदस्य सचिव

8. श्री सी० आर० कृष्णमूर्ति, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग।

5. इस समिति के विचारार्थ विषय, बहुद्देशीय कार्यकर्ता समिति और यप आफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स मैन पावर द्वारा दिए गए सुझावों का पालन करते हुए निम्नलिखित होंगे :—

- (i) व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित पैरामेडिकल काडरो के प्रशिक्षण और रोजगार के कार्यक्रम की जांच करना और इस कार्यक्रम को शीघ्र क्रियान्वित के लिए, यदि आगे आवश्यकता हो तो उपाय सुझाना।
- (ii) समुदाय स्तर के कार्यकर्ताओं के बारे में पहले लिये गए निर्णय के संदर्भ में 'बियरफुट डाक्टरों' के सिद्धांत की जांच करना और उन सशोधनों को सुझाना जिनकी वह आवश्यकता समझते हों, और
- (iii) देश में स्वास्थ्य, पोषण और परिवार नियोजन की बेहतर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित पैरामेडिकल काडरो के साथ एकीकरण के उपाय सुझाना।

6. यह समिति ऐसे अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं से परामर्श कर सकती है जिन्हें वह जरूरी समझे और यह इस अधिवृत्ता की तारीख से तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी।

7. इन अधिकारियों का यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता संबंधी खर्च उसी स्तर से पूरा किया जाएगा जहाँ से उन्हें वेतन मिलता है। गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता वित्त मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार दिया जाएगा। गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते पर होने वाला खर्च, यदि कोई हो, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) के बजट से पूरा किया जाएगा।

8. यह अधिवृत्ता इस मंत्रालय के 15 दिसम्बर, 1976 को इसी संख्या की अधिवृत्ता का अधिनियम करते हुए जारी की जाती है।

[सं० जेड 16018/5/76- की पी एच]

का० रा० कृष्णमूर्ति, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासलय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा मूद्रित तथा
मिथुनप्रकाश, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976